चिकित्सा क्षेत्र से लुप्त होती मानवता

पिछले एक दशक में भारत की स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़े-बड़े कॉरपोरेट घरानों का तेजी से कब्जा हुआ है। कॉरपोरेट अस्पताल बड़े-बड़े शहरों में बड़ी-बड़ी दुकाने खोलते जा रहे हैं और छोटे अस्पताल अपना बोरिया बिस्तर समेटते जा रहे हैं। इससे भी ज्यादा दुखद बात यह है कि चिकित्सा क्षेत्र से मानवता एकदब गायब हो गई है।

■ डॉ. अशोक जैनर

मैं एक भारतीय मूल का डॉक्टर हूं। आजकल इंग्लैंड में डॉक्टरी कर रहा हूं। मैंने काफी देशों की स्वास्थ्य सेवाओं का अध्ययन किया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डिप्लोमा भी प्राप्त किया। रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्रिस्ट से डिग्री प्राप्त की। पिछले एक दशक से मैं भारत की स्वास्थ्य सेवाओं का अध्ययन भारत में जाकर भी तथा टी.वी. व इंटरनेट के माध्यम से कर रहा हूं। एक डॉक्टर होने के कारण, डॉक्टर के कर्त्तव्य तथा एक इंसान होने के नाते मैंने कलम का सहारा लिया। पिछले एक दशक में भारत की स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़े-बड़े कॉरपोरेट घरानों का कब्जा हुआ है। कॉरपोरेट अस्पताल बड़े-बड़े शहरों में बड़ी-बड़ी दुकाने खोलते जा रहे हैं। छोटी-छोटी दुकाने या तो बन्द हो जाएगीं या फिर बड़ी दुकानों के लिए कार्य करने लगेगीं। जितनी बड़ी दुकान उतना बड़ा नाम, उतना बड़ा दाम। इस बड़े नाम व बड़ी दुकान में सबसे अधिक प्रभावित होता है एक गरीब आदमी। जिस देश में लगभग 60-80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, जो अधिकतर मजदूरी व खेती से अपनी जीविका चलाते हैं। इन गरीबों की गरीबी का मजाक उड़ता है जब ये गरीब अस्पताल का बिल नहीं चुका पाते। कई बार गरीब अपने मरीज की लाश अस्पताल में ही छोड़ भाग खड़े होते हैं। क्या कोई इन गरीबों के लिए अपनी दुकान के दाम कम करता है। क्या कोई इन गरीबों के लिए अपनी दुकान शहर छोड़ गांव में ले जाता है। कितने बड़े कॉरपोरेट या सरकारी अस्पताल गांवों में हैं। क्या गांवों के लोगों को स्वास्थ्य सेवा तभी मिलेगी जब वो शहर जाकर अपना घर बार बेचकर स्वास्थ्य सेवाएं खरीद सके।

स्वास्थ्य व शिक्षा किसी भी देश के नागरिक का मूल अधिकार होता है। स्वास्थ्य व शिक्षा सभी के लिए एक समान हो तथा सभी तक पहुंचे। यह किसी भी देश की सरकार का मूल कर्त्तव्य होता है। लेकिन यदि किसी कारण स्वास्थ्य व शिक्षा प्राइवेट हाथों में चली जाए तब प्राइवेट सेक्टर इसको व्यापार में बदल देते हैं। सब को एक समान व सबको एक साथ की जगह यह केवल पैसे वालों की बनकर रह जाती है। जो अधिक दाम देगा उसे पहले तथा अच्छी शिक्षा व अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगीं। ऐसे में मजाक उड़ता है गरीबों की गरीबी का। घर बिकते हैं गरीबों के, जमीने गिरवी रखी जाती हैं। इंसानियत व मानवता केवल किताबों में पढ़ने के लिए है। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप यह अब केवल कहने के लिए रह गया है। यह कैसा अन्याय, कैसी स्वास्थ्य सेवाएं जो गरीबों को बाहर का रास्ता दिखाती हैं। जिस देश में 30 से 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। उनका पैदा होना ही अभिशाप है। उनके लिए स्वास्थ्य या शिक्षा के लिए सोचना शायद उनकी गलती होगी। क्या ये देश, ये सरकार उनके लिए नहीं है। इसके साथ-साथ सबसे बड़ी समस्या पैदा होती जा रही है। प्राइवेट मेडिकल कालेजों के कारण। मेडिकल ट्रेनिंग किसी भी देश की स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ होती है। यदि मेडिकल ट्रेनिंग भी प्राइवेट हाथों में छोड़ दी जाए तब तो उस देश की स्वास्थ्य सेवाओं का बस भगवान ही मालिक है। एक तो करेला उपर से नीम चढ़ा। एक और मेडिकल की ट्रेनिंग का आधार, ट्रेनिंग का स्तर ट्रेनिंग का उपलब्ध होना केवल तथा केवल पैसा हो तब क्या होगा। मेडिकल में ट्रेनिंग का आधार क्षमता नहीं बल्कि पैसा। जो अधिक पैसा देगा वो मेडिकल में प्रवेश पाएगा। चाहें उसमें क्षमता है या नहीं चाहे उसमें डॉक्टर बनने के गुण है या नहीं। बस उसके पास प्रवेश पाने के लिए 50 से 60 लाख डोनेशन होना चाहिए। उसके बाद फिर 30 से 40 लाख फीस। मानों आपने मरीजों की जान से खेलने का लाइसेंस ले लिया। अब सबसे पहले जो पैसा दिया था डोनेशन के रूप में उसे वापस लेने के लिए खेल शुरू होता है। बाजार में जगह-जगह इस प्रकार का लाइसेंस देने की दुकानें प्राइवेट मेडिकल कालेजों के रूप में खुलती जा रही हैं। खुले भी क्यों नहीं क्योंकि यह एक ऐसा व्यापार है जिसमें घाटे का सवाल नहीं है। बड़े-बड़े लोग पैसा लेकर सीट के लिए आगे पीछे भागते हैं। उधार का काम नहीं। ऐसा व्यापार भला क्यों नहीं चलेगा। लेकिन क्या कभी सरकार ने इसका आकलन करने की कोशिश की है कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। डॉक्टर ने बड़ी-बड़ी जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, आदि कराने का एक धंधा बना लिया है। मरीजों को क्या मालूम कि ये जांच केवल पैसा कमाने के लिए हो रही हैं डॉक्टर व जांच करने वालों के बीच बड़ा अच्छा तालमेल चल रहा है तथा मरीज की जेब खाली होती जा रही है। सरकार को चाहिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को सरकारी बनाया जाए तथा सभी मेडिकल कॉलेजों का स्तर एक समान हो। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के लिए सरकार कड़े मापदंड निर्धारित करे। प्रवेश का कन्ट्रोल सरकार अपने पास रखे। धीरे-धीरे इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को सरकारी बनाया जाए। स्वास्थ्य में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार नीति तथा प्रोटोकॉल बनाए। ■■